जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 285 प्रभात जालोर, बुधवार 21 जनवरी, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

यूरोप, भारत के साथ, ''मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स'' करेगा

यूरोपियन कमीशन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयेन से डावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में सार्वजनिक मंच से घोषणा की

- उर्सुला लेयेन के अनुसार, वे तथा यूरोपीयन यूनियन के व्यापारिक समझौतों के मुख्य कार्यकारी भारत जाएंगे तथा भारत के साथ व्यापारिक समझौते को हस्ताक्षरित करेंगे।
- दोनों पार्टियाँ यूरोप व भारत इस समझौते को काफी समय से फाइनल करना चाह रही थीं। पर, ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर उनकी दादागिरी स्वीकार नहीं करने पर अमेरिका द्वारा यूरोपीय देशों के अमेरिका को निर्यात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से यूरोपीय देशों में नया जोश भरा और वे तुरंत भारत से ''ट्रेड डील'' (व्यापारिक समझौता) करने में तत्पर हो गए।
- उर्सुला लेयेन के अनुसार, यह व्यापारिक समझौता विश्व के दो अरब व्यक्तियों को कवर करेगा तथा यह विश्व की जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा है।
- इस ट्रेड डील के बाद, यूरोप के कई उत्पादन, कम टैरिफ के कारण, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो जाएंगे और यूरोप भी भारत की उसके कृषि उत्पादन के बारे में संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि उत्पादों को विशेषकर चीनी को समझौते से दूर रखेगा। भारत की यूरोप के जीआई (ज्योग्रॉफिकल इंडिकेशन) उत्पादों को समझौते में शामिल नहीं करेगा।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। डॉनल्ड ट्रंप द्वारा डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन के लिए यूरोप पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी के जवाब में, यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ एक ऐसे व्यापार समझौते के संपन्न होने की घोषणा की है, जिसने ''सभी व्यापार समझौतों की जननी'' बताया है।

डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने घोषणा की कि वे और आयोग के मुख्य व्यापार वार्ताकार भारत की यात्रा करेंगे, ताकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सके। यह समझौता दोनों महाद्वीपों की लगभग दो अरब आबादी को कवर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय जीडीपी के लगभग एक-चौथाई हिस्से को समेटेगा।

जब अमेरिका अपने सहयोगियों के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तब यूरोप भविष्य के नए विकास केन्द्रों और उभरती आर्थिक शक्तियों के साथ सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भू-अर्थशास्त्र (जियो-इकोनॉमिक्स) की इस नई शक्ति-राजनीति में भारत, यूरोपीय संघ की रणनीतिक गणना में एक केन्द्रीय स्थान पर आ गया है। दोनों पक्ष लंबे समय से इस समझौते पर काम कर रहे थे, लेकिन इस समय इसे तेज़ी से आगे बढ़ाया गया, ताकि अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुख, बैंकर, वित्तपोषक और अंतर्राष्ट्रीय निर्णयकर्ता एकत्र होते हैं, से वॉन डेर लेयेन ने एक ऐसा संदेश देने की कोशिश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पार्टी में नितिन नबीन मेरे बॉस हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को नितिन नबीन (45) को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से जुड़े मामलों में युवा नेता अब उनके बॉस होंगे।

भाजपा ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में नितिन नबीन को औपचारिक रूप से अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष

- प्र.मंत्री मोदी ने नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए यह भी कहा कि ''मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आप मेरे अध्यक्ष हैं।''

घोषित किया। उन्हें इस पद पर निर्विरोध चुना गया।

नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने 45 वर्षीय नितिन नवीन को ''मिलेनियल'' बताते हुए कहा कि वे उस पीढ़ी से आते हैं, जिसने भारत में बड़े बदलावों को देखा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''जब पार्टी के मामलों की बात आती है, तो माननीय नितिन नबीन जी..मैं एक कार्यकर्ता हूं और आप मेरे बॉस हैं।''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा की ओएमआर शीट में हेराफेरी करने वाले 7 गिरफ्तार

एसओजी ने कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारियों व ओएमआर शीट स्कैन करने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों को पकड़ा

- एसओजी की जाँच में सामने आया कि कंपनी के कार्मिक ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद कम्प्यूटर सिस्टम डेटा में छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के नम्बर बढ़ा देते थे। इसके आधार पर कई अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करवाया गया।

जयपुर, 20 जनवरी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारी शामिल हैं। वहीं ओएमआर शीट स्कैन करने वाली कंपनी के दो कर्मचारियों और एक महिला अभ्यर्थी को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला साल 2018 में हुई कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। अब इन तीन भर्ती परीक्षाओं में शामिल 38 अभ्यर्थी भी एसओजी के राडार पर हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि साल 2018 में हुई महिला अधिकारिता विभाग सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेरफेर कर नंबर बढ़ाने के आरोप में उप निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर व तकनीकी प्रमुख) संजय माथुर, प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल, ओएमआर शीट की स्कैनिंग करने वाली कंपनी राभव लिमिटेड, नई दिल्ली के शादान खान व विनोद कुमार गौड़ और महिला अभ्यर्थी पूनम माथुर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के 38 अभ्यर्थी भी एसओजी के राडार पर हैं। आरोपियों ने न केवल अपने परिचित अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करवाया, बल्कि ओएमआर शीट में हेराफेरी कर लाखों रुपए भी बटोरे हैं। किस अभ्यर्थी से कितने रुपए लिए गए, इसे लेकर जांच जारी है।

एसओजी एडीजी ने बताया कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में 3 हजार 212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ये परीक्षाएं 2019 में हुई थी। परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग का काम नई दिल्ली की राभव लिमिटेड को सौंपा गया था। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि कंपनी के कार्मिक ओएमआर शीट की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम के डेटा में छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के नंबर में बढ़ोतरी कर देते थे। इसके आधार पर कई अयोग्य अभ्यर्थियों का भी चयन करवाया गया। एसओजी और चयन बोर्ड ने मूल ओएमआर शीट की दोबारा स्कैनिंग की, तो कई गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। वहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रशासन यह निर्णय नहीं ले सकता, कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं'

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह सवाल उठाकर पूरे मसले का राजनीतिकरण कर दिया

- कांग्रेस के पवन खेड़ा व सपा के अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिए और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए।
- असल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा है कि वे खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर उनका कोई अधिकारिक अभिषेक नहीं हुआ है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के बीच टकराव ने राजनीतिक रूप ले लिया है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें एक नोटिस जारी किए जाने के बाद विवाद और गहरा गया, जिसमें उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि वे स्वयं को शंकराचार्य क्यों कहते हैं।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित, विपक्षी दल शंकराचार्य के समर्थन में सामने आ गये हैं। इस बीच, शंकराचार्य पिछले 48 घंटों से धरने पर बैठे हैं। राज्य प्रशासन ने उन्हें प्रयागराज में संगम पर, परंपरा के अनुसार पालकी में बैठकर, शाही स्नान करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। शंकराचार्य का दावा है कि यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिसमें गोमांस का मुद्दा उठाना, राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को अधूरा बताना और माघ मेले में अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना शामिल है।

माघ मेले के दौरान विवाद तब और बढ़ गया, जब राज्य सरकार ने शंकराचार्य परंपरा के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शाही स्नान की अनुमति देने से मना कर दिया और कहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्ट्रीट डॉग्स पर मेनका के पॉडकास्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज़

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की। आवारा कुत्तों

- पॉडकास्ट में मेनका गांधी की टिप्पणियों व बॉडी लैंग्वेज की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आलोचना की और मेनका के वकील से कहा, ये हमारी उदारता है कि हमने इसे ''अवमानना'' नहीं माना है।

के मामले में अदालत की टिप्पणियों को लेकर एक पॉडकास्ट में दिए गए उनके बयान और ''बॉडी लैंग्वेज'' पर अदालत ने गंभीर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि यह अदालत की ''उदारता''

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने ग्रीनलैंड और कैनडा को अमेरिका का हिस्सा बताया

अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिका का एक नक्शा शेयर किया, जिसमें ग्रीनलैंड व कैनडा को अमेरिकन क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया

- ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट की, जिनमें अमेरिका के साम्राज्यवादी इरादों व ताकत का प्रदर्शन किया गया।
- ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक कार्यक्रम में कहा कि डेनमार्क में ग्रीनलैंड को बचाने की ताकत नहीं है, अमेरिका की सेना विश्व में सबसे ताकतवर है। उनका यह बयान संकेत देता है कि वे सैन्य हमला भी कर सकते हैं।
- इसी बीच ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी लिबरल डैमोक्रेटिक पार्टी के नेता एड डेवी ने कहा कि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और गुंडे हैं तथा अमेरिका के सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति हैं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। अपनी नव-औपनिवेशिक पागल महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक कार्टोग्राफिक आक्रमण शुरू कर दिया है। उन्होंने ''ट्रुथ सोशल'' पर कई संदेश पोस्ट किए हैं, जिनमें यह संकेत दिया गया है कि ग्रीनलैंड अब संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है।

एक पोस्ट में, ट्रंप ने अमेरिकी मानचित्र की तस्वीर साझा की, जिसमें ग्रीनलैंड और कैनडा को अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था।

पोस्ट में ट्रंप को ओवल कार्यालय में बैठे हुए दिखाया गया है, जहां वे नाटो के कई नेताओं के साथ हैं, जिनमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन तथा अन्य नेता शामिल हैं।

ट्रुथ सोशल की एक अन्य पोस्ट में, ट्रंप उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ ग्रीनलैंड में अमेरिकी ध्वज फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास में एक साइनबोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है: ''ग्रीनलैंड, अमेरिकी क्षेत्र, स्थापित 2026।''

इस बीच, अमेरिकी विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए, ब्रिटेन के एक प्रमुख नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को ''अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर'', ''गंभीर उत्पीड़क'' और ''अमेरिका का अब तक का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति'' करार दिया। यह टिप्पणी उन्होंने ब्रिटिश संसद में की।

लिबरल डेमोक्रेट के नेता एड डेवी, जो ब्रिटेन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, ट्रंप द्वारा इंग्लैंड और उसके यूरोपीय सहयोगियों को ''व्यापार-टैरिफ'' से जुड़ी धमकियों के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे थे,

डेवी ने ट्रंप के राष्ट्रपति काल को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फिक्की की वित्तीय वर्ष 26 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर 2025) की रिपोर्ट काफी उत्साहवर्धक है, भारत के लिए

इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, 91 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के लोग कहते हैं कि इस तिमाही में उनका उत्पादन बढ़ा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 जनवरी। भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। औद्योगिक संगठन एफआईसीसीआई (फिक्की) के नवीनतम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने अब तक का सर्वोच्च स्तर छू लिया है, जो व्यापक अर्थव्यवस्था में बढ़ती गति का संकेत देता है। उद्योग संगठन के 68वें त्रैमासिक विनिर्माण सर्वेक्षण के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्पादन स्तर में वृद्धि या स्थिरता की सूचना दी, जो पिछली तिमाही में 87 प्रतिशत थी। यह तेज सुधार औद्योगिक गतिविधियों में निरंतर पुनरुद्धार और व्यापारिक विश्वास में वृद्धि को दर्शाता है, जिसे हालिया जीएसटी दर कटौतियों से भी आंशिक समर्थन मिला है।

उत्पादन रुझानों में यह सुधार मजबूत घरेलू मांग से भी पुष्ट हुआ। सर्वेक्षण में शामिल 86 प्रतिशत निर्माताओं ने तीसरी तिमाही में ऑर्डर बुक्स के स्थिर रहने पर पिछली तिमाही के मुकाबले बेहतर होने की उम्मीद जताई। इससे संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बावजूद उपभोग और निवेश मांग बनी हुई है। निर्यात का माहौल भी अधिक सकारात्मक हुआ है, जहां 70 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाताओं ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में निर्यात के समान या अधिक रहने की उम्मीद जताई है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय निर्माता धीरे-धीरे बाहरी चुनौतियों का सामना कर पा रहे हैं।

यह सर्वेक्षण, जिसमें पूंजीगत वस्तुएं, धातु, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और वस्त्र सहित आठ प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, दर्शाता है कि औसत क्षमता उपयोग लगभग 75 प्रतिशत है। यह स्तर निरंतर आर्थिक गतिविधि होने और उत्पादन अंतर के धीरे-धीरे कम होने का संकेत देता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)